

भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी

डा० अरविन्द कुमार शुक्ल¹

¹एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्ना० महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर उ०प्र०, भारत

Received: 20 August 2026 Accepted & Reviewed: 28 August 2026, Published: 31 August 2026

Abstract

भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी लोकतांत्रिक शासन की प्रभावशीलता, प्रतिनिधित्व और भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारत की विशाल युवा आबादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाता, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक आंदोलनकारी, डिजिटल नागरिक तथा संभावित राजनीतिक नेतृत्व के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी के स्वरूप, प्रवृत्तियों, निर्धारक तत्वों, अवसरों तथा चुनौतियों का विश्लेषण करना है। अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि पर आधारित है तथा इसमें निर्वाचन आयोग, सरकारी रिपोर्टें, जनगणना, राष्ट्रीय युवा नीति, शोध-पत्रों, पुस्तकों और अन्य द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक जागरूकता, शिक्षा, डिजिटल तकनीक, रोजगार की स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक विश्वास और नेतृत्व के अवसर युवाओं की राजनीतिक सहभागिता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। सोशल मीडिया ने युवाओं को राजनीतिक सूचना, अभिव्यक्ति और ऑनलाइन अभियान के नए अवसर प्रदान किए हैं, किंतु फर्जी समाचार, दुष्प्रचार, राजनीतिक ध्रुवीकरण और डिजिटल असमानता जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि युवा राजनीतिक भागीदारी केवल मतदान तक सीमित न रहकर राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों, नागरिक समाज, स्थानीय शासन और डिजिटल मंचों तक विस्तृत हो रही है। शोध का निष्कर्ष है कि भारतीय लोकतंत्र को अधिक सहभागी, समावेशी और उत्तरदायी बनाने के लिए युवाओं को राजनीतिक शिक्षा, नेतृत्व के अवसर, रोजगार, डिजिटल साक्षरता और संस्थागत संवाद उपलब्ध कराना आवश्यक है। सक्रिय, जागरूक और संवैधानिक मूल्यों से प्रतिबद्ध युवा वर्ग लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

मुख्य शब्द— युवा राजनीतिक भागीदारी, भारतीय लोकतंत्र, युवा मतदाता, राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक समाजीकरण, डिजिटल राजनीति, युवा नेतृत्व, नागरिक सहभागिता

Introduction

भारतीय लोकतंत्र की सफलता केवल संवैधानिक संस्थाओं, निर्वाचन व्यवस्था और राजनीतिक दलों की सक्रियता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि देश की युवा आबादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किस प्रकार और कितनी प्रभावी ढंग से भाग लेती है। युवा किसी भी राष्ट्र की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी का महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि देश की जनसंख्या संरचना में युवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। युवा वर्ग न केवल मतदाता के रूप में लोकतांत्रिक शासन को वैधता प्रदान करता है, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक आंदोलनों, नीति-निर्माण, डिजिटल विमर्श और नागरिक समाज की गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी का आधार प्रदान किया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने भारतीय लोकतंत्र को प्रारम्भ से ही व्यापक जनाधार दिया। संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। 1988 के इकसठवें संविधान संशोधन के पश्चात मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, जिससे करोड़ों युवाओं को औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर मिला। इस परिवर्तन ने भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका को संस्थागत रूप से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। युवाओं की राजनीतिक भागीदारी का अर्थ केवल मतदान करने तक सीमित नहीं है। राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करना, चुनाव प्रचार में भाग लेना, राजनीतिक बैठकों में सहभागिता करना, स्थानीय निकायों की गतिविधियों में सक्रिय होना, जनप्रतिनिधियों से संवाद करना, सार्वजनिक नीतियों पर विचार व्यक्त करना, सामाजिक आंदोलनों में भाग लेना, डिजिटल माध्यमों पर राजनीतिक विमर्श करना, जनहित याचिका अथवा नागरिक अभियानों से जुड़ना और स्वयं राजनीतिक नेतृत्व के लिए आगे आना भी राजनीतिक भागीदारी के विभिन्न रूप हैं। इस दृष्टि से युवा राजनीतिक भागीदारी को सक्रिय नागरिकता की व्यापक अवधारणा के अंतर्गत समझा जाना चाहिए।

भारत में युवा राजनीतिक भागीदारी का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों और युवाओं ने राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं के विस्तार के साथ युवाओं की भूमिका चुनावी राजनीति, छात्र राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में दिखाई दी। 1970 के दशक में छात्र आंदोलनों से लेकर 1990 के दशक के सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों तथा इक्कीसवीं सदी में सोशल मीडिया आधारित राजनीतिक अभियानों तक युवाओं की भागीदारी ने नए रूप ग्रहण किए हैं। आज डिजिटल तकनीक ने राजनीतिक सूचना तक पहुँच को आसान बनाया है और युवा वर्ग को अभिव्यक्ति के नए मंच उपलब्ध कराए हैं। यद्यपि युवाओं की संख्या भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी शक्ति है, फिर भी उनकी राजनीतिक भागीदारी के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। राजनीतिक उदासीनता, बेरोजगारी, शिक्षा और रोजगार के बीच असंतुलन, राजनीति में धन एवं बाहुबल की भूमिका, राजनीतिक दलों में अवसरों की सीमित उपलब्धता, परिवारवाद, जातीय और सामुदायिक ध्रुवीकरण, गलत सूचना, राजनीतिक विमर्श का बढ़ता आक्रामक स्वरूप तथा डिजिटल विभाजन जैसी समस्याएँ युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रभावित करती हैं। इसलिए युवाओं की राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन केवल मतदाता संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए राजनीतिक चेतना, राजनीतिक विश्वास, संस्थागत सहभागिता, डिजिटल नागरिकता, नेतृत्व की आकांक्षा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इस शोध का मूल उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी की प्रकृति, स्वरूप, निर्धारक तत्वों, संभावनाओं तथा चुनौतियों का विश्लेषण करना है। अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि युवा किस सीमा तक मतदान और अन्य लोकतांत्रिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, उनकी राजनीतिक सहभागिता को कौन-से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी कारक प्रभावित करते हैं तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक युवा-अनुकूल और सहभागी बनाने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी की अवधारणा को स्पष्ट करना, युवाओं के राजनीतिक व्यवहार में आए परिवर्तनों का अध्ययन करना, मतदान एवं निर्वाचन प्रक्रिया में युवाओं की भूमिका का विश्लेषण करना,

राजनीतिक दलों एवं छात्र राजनीति में उनकी भागीदारी का परीक्षण करना, सोशल मीडिया तथा डिजिटल तकनीक के प्रभाव का अध्ययन करना, युवाओं की राजनीतिक जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच संबंध को समझना, राजनीतिक भागीदारी में विद्यमान लैंगिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की पहचान करना तथा युवा राजनीतिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना है।

इस शोध में यह परिकल्पना की गई है कि भारतीय युवाओं की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि उनकी राजनीतिक भागीदारी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। दूसरी परिकल्पना यह है कि उच्च शिक्षा तथा राजनीतिक सूचना के बेहतर अवसर युवाओं की लोकतांत्रिक सहभागिता की संभावना को बढ़ाते हैं। तीसरी परिकल्पना के अनुसार डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग से युवाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति और राजनीतिक सूचना तक पहुँच में वृद्धि हुई है, यद्यपि इसका प्रभाव हमेशा सकारात्मक नहीं होता। चौथी परिकल्पना यह है कि बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास युवाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी को कमजोर करते हैं। पाँचवीं परिकल्पना यह है कि जिन युवाओं को राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और नागरिक संस्थाओं में नेतृत्व के अवसर प्राप्त होते हैं, उनमें लोकतांत्रिक सहभागिता की प्रवृत्ति अधिक होती है। छठी परिकल्पना यह है कि सामाजिक पृष्ठभूमि, लिंग, ग्रामीण-शहरी निवास और आर्थिक स्थिति युवाओं की राजनीतिक भागीदारी की प्रकृति को प्रभावित करते हैं।

इस अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है। शोध मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। भारत निर्वाचन आयोग की रिपोर्टें, भारत सरकार के युवा संबंधी दस्तावेजों, जनगणना संबंधी आँकड़ों, राष्ट्रीय युवा नीति, सरकारी रिपोर्टें, संसद एवं विधायी दस्तावेजों, शोध-पत्रों, पुस्तकों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें तथा लोकतांत्रिक भागीदारी से संबंधित उपलब्ध साहित्य का उपयोग किया गया है। जहाँ आवश्यक है, वहाँ उपलब्ध निर्वाचन आँकड़ों और प्रकाशित अध्ययनों के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में ऐतिहासिक, संस्थागत, व्यवहारवादी और समकालीन डिजिटल राजनीतिक सहभागिता के दृष्टिकोणों को समन्वित किया गया है। अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक और विश्लेषणात्मक है। राजनीतिक भागीदारी को केवल मतदान के प्रतिशत के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक रुचि, राजनीतिक ज्ञान, चुनावी सहभागिता, राजनीतिक संगठन से जुड़ाव, नागरिक सक्रियता, सामाजिक आंदोलनों में सहभागिता और डिजिटल राजनीतिक संचार जैसे विभिन्न आयामों में देखा गया है। अध्ययन में उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय द्वितीयक सामग्री को प्राथमिकता दी गई है। तथ्यों की व्याख्या करते समय भारतीय लोकतंत्र की सामाजिक विविधता को ध्यान में रखा गया है।

भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की राजनीतिक भूमिका का ऐतिहासिक आधार स्वतंत्रता आंदोलन में देखा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने विद्यार्थियों और युवाओं में राष्ट्रवाद, स्वाधीनता, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना का विकास किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस और अनेक अन्य नेताओं के आंदोलनों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में युवाओं और विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में युवा राजनीतिक सक्रियता लोकतंत्र की स्थापना के बाद की घटना नहीं है, बल्कि इसका संबंध आधुनिक भारतीय राजनीतिक चेतना के विकास से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय लोकतंत्र के संस्थागत विकास के साथ राजनीतिक भागीदारी का स्वरूप बदलने

लगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने राजनीतिक समानता का संवैधानिक आधार बनाया। प्रारम्भिक दशकों में राजनीतिक दलों और चुनावों के माध्यम से युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ने के अवसर मिले। विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति ने राजनीतिक प्रशिक्षण और नेतृत्व निर्माण का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। छात्र संगठनों ने राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार जैसे प्रश्नों को भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया।

1970 के दशक में छात्र आंदोलनों ने भारतीय राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाला। गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलनों ने राजनीतिक असंतोष को संगठित रूप दिया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन में युवाओं की बड़ी भागीदारी रही। आपातकाल के दौर में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के संघर्ष में भी युवा वर्ग की भूमिका उल्लेखनीय रही। इन अनुभवों ने यह प्रदर्शित किया कि युवा केवल चुनावी राजनीति के निष्क्रिय घटक नहीं हैं, बल्कि वे राजनीतिक परिवर्तन के सक्रिय वाहक भी बन सकते हैं।

1989 के बाद भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय, मंडल राजनीति, आर्थिक उदारीकरण, पहचान की राजनीति और गठबंधन राजनीति के उभार ने युवाओं के राजनीतिक व्यवहार को नए रूप दिए। शिक्षा और रोजगार के प्रश्नों के साथ सामाजिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, समान अवसर और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे युवाओं के राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण बने। आर्थिक उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र, वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद और नई तकनीक के विस्तार ने युवाओं की आकांक्षाओं को भी प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप युवा राजनीति में रोजगार, उद्यमिता, शिक्षा, कौशल, डिजिटल अवसर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों का महत्व बढ़ा।

इक्कीसवीं सदी में इंटरनेट और सोशल मीडिया के विस्तार ने युवा राजनीतिक भागीदारी की प्रकृति को गहराई से प्रभावित किया है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने राजनीतिक सूचना के प्रसार और राजनीतिक अभिव्यक्ति के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। अब राजनीतिक संदेश केवल पारंपरिक समाचार माध्यमों या राजनीतिक सभाओं के माध्यम से नहीं पहुँचते, बल्कि युवा स्वयं सामग्री तैयार करके उसे व्यापक स्तर पर प्रसारित कर सकते हैं। डिजिटल माध्यमों ने राजनीतिक संचार को अधिक तात्कालिक, सहभागी और नेटवर्क आधारित बनाया है।

डिजिटल राजनीतिक भागीदारी का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इससे युवाओं को अपने विचार व्यक्त करने के लिए अपेक्षाकृत कम लागत वाला मंच मिला है। कोई युवा किसी सामाजिक समस्या पर पोस्ट लिख सकता है, वीडियो बना सकता है, ऑनलाइन अभियान चला सकता है, जनप्रतिनिधि को टैग करके प्रश्न पूछ सकता है अथवा किसी सार्वजनिक मुद्दे पर डिजिटल समर्थन जुटा सकता है। इससे राजनीतिक भागीदारी की पारंपरिक सीमाएँ कुछ हद तक कमजोर हुई हैं। हालांकि केवल ऑनलाइन अभिव्यक्ति को वास्तविक राजनीतिक प्रभाव के समान नहीं माना जा सकता। डिजिटल सक्रियता तभी अधिक प्रभावी होती है जब वह वास्तविक नागरिक गतिविधियों, संगठनात्मक भागीदारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं से संवाद में परिवर्तित हो। युवा मतदाता भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के लिए विशेष महत्व रखते हैं। 18 वर्ष की आयु में मताधिकार प्राप्त होने के कारण बड़ी संख्या में युवा पहली बार मतदाता बनते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पंजीकरण, मतदाता जागरूकता और चुनावी भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वीप जैसे कार्यक्रम

संचालित किए गए हैं। प्रथम बार मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतदान केवल राजनीतिक प्रतिनिधि के चयन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह नागरिक समानता, राजनीतिक उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक वैधता का महत्वपूर्ण माध्यम है। फिर भी मतदान और व्यापक राजनीतिक भागीदारी के बीच अंतर करना आवश्यक है। कोई युवा मतदान कर सकता है, परन्तु राजनीतिक दल की गतिविधियों में भाग न ले; राजनीतिक मुद्दों पर जानकारी रख सकता है, लेकिन चुनाव प्रचार में भाग न ले, सोशल मीडिया पर सक्रिय हो सकता है, लेकिन मतदान न करे। इसलिए युवा राजनीतिक सहभागिता बहुआयामी प्रक्रिया है। मतदान उसका एक महत्वपूर्ण घटक है, सम्पूर्ण राजनीतिक भागीदारी नहीं।

युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक राजनीतिक जागरूकता है। जिन युवाओं को संविधान, शासन व्यवस्था, निर्वाचन प्रक्रिया, राजनीतिक दलों, सार्वजनिक नीतियों और नागरिक अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है, उनमें राजनीतिक सहभागिता की संभावना सामान्यतः अधिक होती है। राजनीतिक शिक्षा केवल पाठ्यक्रम का विषय नहीं होनी चाहिए। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों, चुनावी प्रक्रिया, मीडिया साक्षरता और सार्वजनिक नीति पर व्यावहारिक शिक्षा युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी के बीच संबंध जटिल लेकिन महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा राजनीतिक जानकारी और आलोचनात्मक सोच के अवसर बढ़ा सकती है। विश्वविद्यालय युवाओं को विभिन्न विचारधाराओं, सामाजिक समूहों और सार्वजनिक मुद्दों के साथ संवाद का अवसर प्रदान करते हैं। वाद-विवाद, छात्र संसद, मॉडल संसद, युवा संसद, सेमिनार और सामुदायिक गतिविधियाँ राजनीतिक सामाजिककरण को मजबूत करती हैं। परन्तु केवल औपचारिक शिक्षा राजनीतिक भागीदारी की गारंटी नहीं देती। यदि शिक्षा व्यवस्था में नागरिक चेतना, आलोचनात्मक चिंतन और सामाजिक उत्तरदायित्व का समावेश न हो, तो डिग्री प्राप्त करना आवश्यक रूप से सक्रिय नागरिकता में परिवर्तित नहीं होता। रोजगार और आर्थिक स्थिति भी युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं। बेरोजगारी, अल्परोजगार और आर्थिक असुरक्षा युवाओं में राजनीतिक असंतोष को बढ़ा सकते हैं। दूसरी ओर आर्थिक रूप से स्वतंत्र युवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अधिक समय और संसाधन जुटा सकते हैं। रोजगार की अनिश्चितता कई युवाओं को राजनीतिक संगठनों से दूरी बनाए रखने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। इसलिए युवा राजनीतिक भागीदारी को रोजगार और आर्थिक अवसरों के व्यापक संदर्भ से अलग करके नहीं समझा जा सकता।

ग्रामीण और शहरी युवाओं की राजनीतिक भागीदारी में भी कुछ अंतर दिखाई देते हैं। शहरी युवाओं को डिजिटल तकनीक, उच्च शिक्षा, समाचार माध्यमों और संगठित नागरिक संस्थाओं तक अपेक्षाकृत अधिक पहुँच मिल सकती है। ग्रामीण युवाओं की राजनीतिक भागीदारी स्थानीय निकायों, पंचायतों, सामुदायिक संगठनों और स्थानीय मुद्दों के माध्यम से अधिक प्रत्यक्ष हो सकती है। पंचायत चुनावों ने ग्रामीण युवाओं को स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व के अवसर उपलब्ध कराए हैं। डिजिटल तकनीक के प्रसार के कारण ग्रामीण-शहरी राजनीतिक सूचना अंतर धीरे-धीरे कम हुआ है, लेकिन डिजिटल विभाजन अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। महिला युवाओं की राजनीतिक भागीदारी का प्रश्न विशेष महत्व रखता है। भारत में महिलाओं की चुनावी भागीदारी में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। अनेक राज्यों में महिला मतदाताओं की सक्रियता बढ़ी है। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण ने राजनीतिक नेतृत्व

का आधार विस्तृत किया है। इससे युवा महिलाओं के लिए राजनीतिक नेतृत्व की संभावनाएँ भी बढ़ सकती हैं। फिर भी पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, घरेलू जिम्मेदारियाँ, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक हिंसा और डिजिटल उत्पीड़न जैसी बाधाएँ युवा महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित कर सकती हैं।

जाति, वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूमि भी युवाओं के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है। भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में जाति और समुदाय राजनीतिक पहचान के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। वंचित और हाशिए के समूहों के युवा सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और समान अवसर के मुद्दों के माध्यम से राजनीति से जुड़ते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति का उद्देश्य केवल बहुमत का शासन नहीं, बल्कि सभी सामाजिक समूहों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। इसलिए युवा राजनीतिक भागीदारी का मूल्यांकन सामाजिक समावेशन के आधार पर किया जाना चाहिए।

राजनीतिक दल युवाओं की भागीदारी के महत्वपूर्ण संस्थागत माध्यम हैं। अधिकांश राजनीतिक दल युवा प्रकोष्ठों के माध्यम से युवाओं को संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ते हैं। युवा कार्यकर्ता चुनाव प्रचार, जनसंपर्क, सोशल मीडिया अभियान और संगठन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परन्तु राजनीतिक दलों में युवाओं की वास्तविक निर्णयकारी भूमिका अभी भी एक चुनौती है। युवा कार्यकर्ताओं को केवल प्रचार और भीड़ जुटाने तक सीमित रखने के बजाय नीति निर्माण, उम्मीदवार चयन, संगठनात्मक निर्णय और नेतृत्व विकास में अवसर देना लोकतांत्रिक राजनीति को अधिक सहभागी बना सकता है। भारतीय लोकतंत्र में परिवारवाद का प्रश्न भी युवा राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा है। राजनीतिक परिवारों से आने वाले युवाओं को संसाधन, नेटवर्क और राजनीतिक पहचान के कारण अपेक्षाकृत आसान प्रवेश मिल सकता है। दूसरी ओर सामान्य सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं के लिए राजनीति में प्रवेश अधिक कठिन हो सकता है। लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता तभी बढ़ेगी जब राजनीतिक दल योग्यता, संगठनात्मक अनुभव, जनसेवा और सामाजिक प्रतिबद्धता के आधार पर युवाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करेंगे। छात्र राजनीति युवाओं के राजनीतिक प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय राजनीतिक विचारों के संवाद, नेतृत्व, संगठन क्षमता और लोकतांत्रिक बहस के मंच हो सकते हैं। छात्र राजनीति के सकारात्मक पक्ष में नेतृत्व निर्माण, सार्वजनिक मुद्दों पर जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रशिक्षण शामिल हैं। इसके नकारात्मक पक्ष में हिंसा, बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप, धनबल, गुटबाजी और शैक्षणिक वातावरण का राजनीतिकरण शामिल हो सकता है। इसलिए छात्र राजनीति को समाप्त करने के बजाय उसे स्वस्थ, पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है। युवाओं की राजनीतिक भागीदारी में नागरिक समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। गैर-सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएँ, सामाजिक आंदोलन और सामुदायिक संगठन युवाओं को जनहित के मुद्दों से जोड़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता, मानवाधिकार, शिक्षा, भ्रष्टाचार विरोध, स्वास्थ्य, डिजिटल अधिकार और स्थानीय विकास जैसे विषय युवाओं को पारंपरिक दलगत राजनीति से अलग नागरिक राजनीति के माध्यमों से जोड़ते हैं। इससे लोकतंत्र का क्षेत्र व्यापक होता है।

भारतीय युवाओं में राजनीतिक भागीदारी का एक नया आयाम ऑनलाइन नागरिकता है। डिजिटल मंचों पर राजनीतिक चर्चा ने सूचना और अभिव्यक्ति को अधिक लोकतांत्रिक बनाया है, लेकिन इसके साथ गलत सूचना और दुष्प्रचार की समस्या भी बढ़ी है। फर्जी समाचार, भ्रामक वीडियो, संदर्भ से बाहर की सामग्री,

बॉट आधारित प्रचार और राजनीतिक ध्रुवीकरण युवाओं के राजनीतिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल साक्षरता लोकतांत्रिक नागरिकता का अनिवार्य हिस्सा बनती जा रही है। राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक विश्वास के बीच भी महत्वपूर्ण संबंध है। यदि युवा संसद, राजनीतिक दलों, प्रशासन, निर्वाचन व्यवस्था और न्यायिक संस्थाओं को विश्वसनीय मानते हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी मजबूत हो सकती है। इसके विपरीत भ्रष्टाचार, राजनीतिक अवसरवाद, आपराधिक राजनीति, चुनावी वादों और नीतिगत परिणामों के बीच अंतर तथा संस्थागत असमानता की धारणा युवाओं में निराशा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए युवा सहभागिता बढ़ाने के लिए संस्थागत विश्वास को मजबूत करना भी आवश्यक है। भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि युवा पारंपरिक राजनीतिक सीमाओं को चुनौती देने वाली नई राजनीतिक भाषा और नए मुद्दे सामने ला रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी नवाचार, डिजिटल अधिकार, लैंगिक समानता, मानसिक स्वतंत्रता, शहरी सुविधाएँ और वैश्विक अवसर जैसे विषय युवा राजनीतिक चेतना का हिस्सा बन रहे हैं। इससे राजनीति का एजेंडा अधिक भविष्य उन्मुख हो सकता है। हालाँकि युवा राजनीति में भावनात्मकता और तात्कालिकता का प्रभाव भी देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के कारण राजनीतिक प्रतिक्रिया अत्यंत तेज हो गई है। किसी घटना पर कुछ घंटों में व्यापक डिजिटल अभियान शुरू हो सकता है। यह लोकतांत्रिक दबाव निर्माण का प्रभावी माध्यम है, लेकिन बिना तथ्य-जाँच के प्रतिक्रिया राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव को भी बढ़ा सकती है। इसलिए युवा राजनीतिक सक्रियता को तथ्य आधारित, संवैधानिक और संवादपरक बनाना आवश्यक है।

इस शोध के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को तीन व्यापक स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला, पारंपरिक संस्थागत भागीदारी, जिसमें मतदान, राजनीतिक दलों की सदस्यता और चुनावी गतिविधियाँ शामिल हैं। दूसरा, सामुदायिक एवं सामाजिक भागीदारी, जिसमें नागरिक संगठन, सामाजिक आंदोलन और स्थानीय शासन शामिल हैं। तीसरा, डिजिटल भागीदारी, जिसमें सोशल मीडिया विमर्श, ऑनलाइन अभियान और डिजिटल राजनीतिक संचार शामिल हैं। समकालीन युवा इन तीनों स्तरों को एक-दूसरे से जोड़ते हुए राजनीतिक सक्रियता के नए रूप विकसित कर रहे हैं। उपलब्ध साहित्य और द्वितीयक आँकड़ों के विश्लेषण से पहली परिकल्पना को पर्याप्त समर्थन मिलता है कि राजनीतिक जागरूकता युवाओं की भागीदारी को प्रभावित करती है। राजनीतिक जानकारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ रखने वाले युवा राजनीतिक गतिविधियों में अपेक्षाकृत अधिक रुचि दिखाते हैं। दूसरी परिकल्पना को भी व्यापक रूप से समर्थन मिलता है कि शिक्षा और सूचना तक पहुँच राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाती है। तथापि शिक्षा और भागीदारी का संबंध रैखिक नहीं है; शिक्षा के साथ राजनीतिक विश्वास और नागरिक अवसरों का होना भी आवश्यक है। तीसरी परिकल्पना के संबंध में पाया जाता है कि डिजिटल माध्यमों ने युवाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को व्यापक बनाया है। सोशल मीडिया ने राजनीतिक सूचना और विमर्श की गति बढ़ाई है, लेकिन इसके साथ गलत सूचना और ध्रुवीकरण की चुनौती भी उत्पन्न हुई है। अतः डिजिटल माध्यम राजनीतिक भागीदारी का अवसर और जोखिम दोनों प्रस्तुत करते हैं। चौथी परिकल्पना के संदर्भ में आर्थिक असुरक्षा और बेरोजगारी को राजनीतिक असंतोष के महत्वपूर्ण स्रोतों में माना जा सकता है। आर्थिक अवसरों की कमी युवाओं में शासन और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति असंतोष बढ़ा सकती है। हालाँकि आर्थिक असुरक्षा हमेशा राजनीतिक निष्क्रियता में परिवर्तित नहीं होती; कई बार यह आंदोलनों और

विरोध प्रदर्शनों को भी प्रेरित करती है। पाँचवीं परिकल्पना को भी समर्थन मिलता है कि राजनीतिक संगठनों में नेतृत्व के अवसर युवा सहभागिता को बढ़ाते हैं। यदि युवाओं को केवल कार्यकर्ता या प्रचारक की भूमिका दी जाती है, तो उनकी दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता सीमित हो सकती है। इसके विपरीत निर्णय-निर्माण और नेतृत्व के अवसर राजनीतिक क्षमता का विकास करते हैं। छठी परिकल्पना भी महत्वपूर्ण है। लिंग, ग्रामीण-शहरी निवास, सामाजिक पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति युवाओं के राजनीतिक अनुभवों को प्रभावित करते हैं। इसलिए युवा राजनीतिक भागीदारी को एक समान श्रेणी मानना उचित नहीं है। युवा वर्ग स्वयं सामाजिक और आर्थिक रूप से विविध है।

अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र में युवा केवल भविष्य के नागरिक नहीं हैं, बल्कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के सक्रिय सहभागी हैं। उनकी भूमिका मतदान से आगे बढ़कर नेतृत्व, नागरिक समाज, डिजिटल राजनीति और नीति-विमर्श तक विस्तृत हो रही है। भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की गुणवत्ता इस बात पर काफी हद तक निर्भर करेगी कि युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में कितनी सार्थक भागीदारी प्राप्त होती है। युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए विद्यालय और उच्च शिक्षा के स्तर पर व्यावहारिक नागरिक एवं संवैधानिक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जाए। संविधान, चुनाव प्रक्रिया, संसद, स्थानीय शासन, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की शिक्षा को केवल सैद्धांतिक विषय न बनाकर व्यवहारिक गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। प्रथम बार मतदाताओं के लिए नियमित और संस्थागत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएँ। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मतदाता पंजीकरण, मतदान प्रक्रिया तथा जिम्मेदार मतदान पर विशेष अभियान चलाए जा सकते हैं। राजनीतिक दलों को युवा नेतृत्व के लिए स्पष्ट और पारदर्शी आंतरिक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। युवाओं को केवल चुनावी प्रचार तक सीमित रखने के बजाय नीति निर्माण और संगठनात्मक निर्णयों में वास्तविक भूमिका दी जानी चाहिए। छात्र राजनीति में लोकतांत्रिक आचार-संहिता को प्रभावी बनाया जाए। हिंसा, धनबल और बाहरी हस्तक्षेप को नियंत्रित करते हुए छात्र संगठनों को स्वस्थ राजनीतिक प्रशिक्षण का माध्यम बनाया जाना चाहिए। युवा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए सुरक्षित और समान अवसर सुनिश्चित किए जाएँ। महिला नेतृत्व प्रशिक्षण, राजनीतिक शिक्षा और डिजिटल सुरक्षा कार्यक्रम उपयोगी हो सकते हैं। डिजिटल एवं मीडिया साक्षरता को उच्च शिक्षा का अनिवार्य घटक बनाया जाए। युवाओं को फर्जी समाचार, डीपफेक, दुष्प्रचार और भ्रामक राजनीतिक सामग्री की पहचान करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ग्रामीण युवाओं को स्थानीय शासन और पंचायत व्यवस्था में अधिक सक्रिय भूमिका के अवसर दिए जाएँ। ग्रामसभा, सामाजिक अंकेक्षण और स्थानीय विकास योजनाओं में युवा सहभागिता बढ़ाई जानी चाहिए। युवाओं की आर्थिक समस्याओं, विशेषकर बेरोजगारी और कौशल-असंगति को राजनीतिक भागीदारी की व्यापक नीति से जोड़ा जाए। रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ने से युवाओं की सामाजिक और राजनीतिक क्षमता भी मजबूत हो सकती है। युवा संसद, मॉडल संसद, मॉडल विधानसभा और स्थानीय शासन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित बनाया जाए। इससे युवाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। राजनीतिक दलों और सार्वजनिक संस्थाओं को युवाओं से नियमित नीति संवाद स्थापित करना चाहिए। युवा नीति परिषद, विश्वविद्यालय संवाद और डिजिटल परामर्श जैसे माध्यम विकसित किए जा सकते हैं। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए। उम्मीदवार चयन और नेतृत्व विकास में युवा, महिला तथा

सामाजिक रूप से विविध समूहों को उचित अवसर मिलने चाहिए। युवाओं को नागरिक समाज और सामुदायिक विकास गतिविधियों से जोड़ा जाए। पर्यावरण, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल जागरूकता और सामाजिक सेवा के कार्यक्रम सक्रिय नागरिकता के व्यावहारिक विद्यालय बन सकते हैं। युवाओं की राजनीतिक भागीदारी पर नियमित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अध्ययन कराए जाएँ। निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को युवा मतदाताओं के व्यवहार, राजनीतिक विश्वास, डिजिटल भागीदारी, लैंगिक अंतर तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर दीर्घकालिक अध्ययन विकसित करना चाहिए।

निष्कर्षतया समग्र रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीवंतता, प्रतिनिधित्व और भविष्य की दिशा का महत्वपूर्ण सूचक है। भारत का युवा वर्ग संख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ विचार, तकनीक, ऊर्जा और परिवर्तन की क्षमता से भी संपन्न है। यदि इस ऊर्जा को संवैधानिक मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ जोड़ा जाए तो युवा भारत की लोकतांत्रिक शक्ति को नई दिशा दे सकते हैं। युवा राजनीतिक सहभागिता को केवल चुनावी आँकड़ों में मापना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक लोकतांत्रिक भागीदारी तब मानी जाएगी जब युवा सूचना प्राप्त करें, प्रश्न पूछें, संवाद करें, मतदान करें, सार्वजनिक संस्थाओं से जवाबदेही माँगें, सामाजिक समस्याओं के समाधान में योगदान दें और आवश्यकता पड़ने पर नेतृत्व की जिम्मेदारी स्वीकार करें। इसी अर्थ में युवा लोकतंत्र के केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि उसके निर्माता और संरक्षक हैं। भारतीय लोकतंत्र के सामने वर्तमान समय में तकनीकी परिवर्तन, सामाजिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय संकट और वैश्वीकरण जैसी अनेक चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल संस्थागत सुधारों से संभव नहीं है; इसके लिए ऐसी युवा पीढ़ी की आवश्यकता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग, तथ्यपरक चिंतन से युक्त, संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध हो। युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना इसलिए केवल राजनीतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य शर्त है।

अंततः भारतीय लोकतंत्र का भविष्य युवाओं की संख्या से नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक गुणवत्ता, नागरिक चेतना और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता से निर्धारित होगा। यदि युवाओं को समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण राजनीतिक शिक्षा, रोजगार, नेतृत्व के अवसर, सुरक्षित डिजिटल वातावरण और संस्थागत संवाद उपलब्ध कराया जाता है, तो वे भारतीय लोकतंत्र को अधिक सहभागी, उत्तरदायी, समावेशी और नवोन्मेषी बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अतः युवा राजनीतिक भागीदारी को लोकतंत्र की परिधि में नहीं, बल्कि उसके केंद्रीय आधार के रूप में स्वीकार करना समय की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची—

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Barnes, S. H., & Kaase, M. (1979). *Political action: Mass participation in five Western democracies*. Sage Publications.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Dalton, R. J. (2017). *The participation gap: Social status and political inequality*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198733607.001.0001>

RESEARCH WORK

A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal

Volume 02, Issue 08, August 2026

DOI- <https://doi.org/10.5281/zenodo.22202328>

International IDEA. (2018). *Youth participation in political processes: Second annual summer school for young leaders from African political parties*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: Social media, political participation and civic engagement. *Information, Communication & Society*, 17(2), 143–150. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571>

Xenos, M., Vromen, A., & Loader, B. D. (2014). The great equalizer? Patterns of social media use and youth political engagement in three advanced democracies. *Information, Communication & Society*, 17(2), 151–167. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871318>

Kahne, J., & Bowyer, B. (2018). The political significance of social media activity and social networks. *Political Communication*, 35(3), 470–493. <https://doi.org/10.1080/10584609.2018.1426662>

Levy, B. L. M., & Akiva, T. (2019). Motivating political participation among youth: An analysis of factors related to adolescents' political engagement. *Political Psychology*. <https://doi.org/10.1111/pops.12578>

McLeod, J. M., Scheufele, D. A., & Moy, P. (1999). Community, communication, and participation: The role of mass media and interpersonal discussion. *Political Communication*, 16(3), 315–336. <https://doi.org/10.1080/105846099198659>

Mustapha, L. K., & Omar, B. (2020). Do social media matter? Examining social media use and youths' political participation during the 2019 Nigerian general elections. *The Round Table*, 109(4), 441–457. <https://doi.org/10.1080/00358533.2020.1788766>

United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (2018). *World youth report 2018: Youth and the 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations. ISBN 978-92-1-130349-0.

UNESCO. (2015). *Global citizenship education: Topics and learning objectives*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. ISBN 978-92-3-100102-4. <https://doi.org/10.54675/DRHC3544>

Election Commission of India. (2026). *Systematic Voters' Education and Electoral Participation (SVEEP)*. Election Commission of India.

World Bank. (2006). *World development report 2007: Development and the next generation*. World Bank.

शुक्ल, अ. कु. (2026). भारतीय लोकतंत्र में डिजिटल मीडिया और राजनीतिक सहभागिता: नागरिक चेतना एवं जनमत निर्माण का अध्ययन. *Idealistic Journal of Advanced Research in Progressive Spectrums (IJARPS)*, 5(05), 125–134. <https://doi.org/10.82471/c99s5-tvq73>

शुक्ल, अ. कु. (2025). विकसित भारत 2047: एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की संभावनाएं. *Idealistic Journal of Advanced Research in Progressive Spectrums (IJARPS)*, 4(02), 126–135. [आधिकारिक IJARPS लेख](#)

शुक्ल, अ. कु. (2023). विनोबा भावे और भूदान आंदोलन. *Idealistic Journal of Advanced Research in Progressive Spectrums (IJARPS)*, 2(02), 40–46. [आधिकारिक IJARPS लेख](#)

शुक्ल, अ. कु. (2025). कश्मीर नीति: अनुच्छेद 370 हटने के बाद की स्थिति. *Idealistic Journal of Advanced Research in Progressive Spectrums (IJARPS)*, 4(09), 74–90. [आधिकारिक IJARPS लेख](#)

शुक्ल, अ. कु. (2023). आत्मनिर्भर भारत की चुनौतियाँ और मुद्दे. *International Journal of Advanced Research in Multidisciplinary Sciences (IJARMS)*, 6(2), 93–104. [आधिकारिक IJARMS स्रोत](#)

RESEARCH WORK**A Monthly, Open Access, Peer Reviewed International Research Journal****Volume 02, Issue 08, August 2026****DOI- <https://doi.org/10.5281/zenodo.22202328>**

शुक्ल, अ. कु. (2023). महिला मानवाधिकार और घरेलू हिंसा. *International Journal of Advanced Research in Multidisciplinary Sciences (IJARMS)*, 6, 91–100. [आधिकारिक IJARMS स्रोत](#)

शुक्ल, अ. कु. (2023). 21वीं सदी में भारत के समक्ष चुनौतियां. *International Journal of Advanced Research in Multidisciplinary Sciences (IJARMS)*, 6(1), 192–198. [आधिकारिक IJARMS स्रोत](#)